International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 6, September-October 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

लघु उद्योग सेवा संस्थान का औद्योगिक विकास में योगदान

डॉ. हेमेंद्र गर्ग[1], डॉ. सौम्या शर्मा[2]

[1]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, आर .बी .एस. कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश
[2]सह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, आर .बी .एस. कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश

सार

भारत में लघु उद्योगों का समर्थन करने वाली संस्थाओं के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है। औद्योगीकरण किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लेकिन प्रत्येक विकासशील देश द्वारा आवश्यक औद्योगीकरण का प्रकार भिन्न होता है। किसी देश की औद्योगिक संरचना में बड़े, मध्यम और लघु उद्योग शामिल हैं। इन तीन प्रकार के औद्योगीकरण में, किसी देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है।

भारत में लघु उद्योगों का समर्थन करने वाली कुछ संस्थाएँ हैं: -
1. लघु उद्योग बोर्ड (SSIB) 2. लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) 3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) 4. लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISIS) 5. विशिष्ट संस्थान

6. उद्योग निदेशालय 7. राज्य लघु उद्योग विकास निगम (SSIDCs) 8. औद्योगिक संपदा 9. जिला उद्योग केंद्र (DIC) 10। तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओएस) 11. वाणिज्यिक बैंक 12. राज्य वित्तीय निगम[1]

13. लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) 14. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) 15. उद्यमी मार्गदर्शन ब्यूरो (EGB) 16. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) 17. लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (SIETI)) 18. लघु उद्योग विकास निगम (SIDCO)।

भारत सरकार ने 1954 में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों और नीतियों पर सलाह देने के लिए लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड को केंद्रीय लघु उद्योग बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। SSIB में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य वित्तीय निगम और गैर-अधिकारी सहित 50 सदस्य होते हैं।

How to cite this paper: Dr. Hemendra Garg | Dr. Soumya Sharma "Contribution of Small Industries Service Institute to Industrial Development" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-6, October 2022, pp.1504-1518, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52114.pdf

IJTSRD52114

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

केंद्रीय उद्योग मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड का मुख्य कार्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और लघु उद्योग सेवा संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करना है। बोर्ड देश में लघु उद्योगों के लिए संशोधनों या सुधारों की सलाह भी देता है। बोर्ड की स्थायी समिति है और लघु उद्योग विकास आयुक्त नामक एक अधिकारी है।

SSIB मुख्य रूप से उन लघु इकाइयों के विकास से संबंधित है, जिनके लिए अलग-अलग बोर्ड स्थापित किए गए हैं जैसे, हस्तनिर्मित कागज, ऊन, गुड़, खांडसारी, चावल की भूसी, मधुमक्खी-पालन, आदि। बोर्ड ने ऋण की उदार शर्तों को अपनाया है। छोटे पैमाने की इकाइयों के लिए। हाल के वर्षों में बोर्ड ने विशेष रूप से ब्याज दरों पर ग्राम, कुटीर, छोटी और लघु-स्तरीय इकाइयों के लिए धन के प्रवाह को बढ़ाने के उपाय किए हैं।[2]

इन विशिष्ट उपायों में शामिल हैं:

1. कारीगरों, गाँव और कुटीर उद्योगों को बैंक क्रेडिट को उपकरण या कार्यशील पूंजी या दोनों के लिए समग्र ऋण के रूप में माना जाएगा। लेकिन एक चुकौती अवधि या 7 से 10 साल या उससे अधिक के साथ क्रेडिट की अधिकतम सीमा रुपये पर तय की गई है। केवल 25000 रु।
2. सभी सावधि ऋणों के लिए ब्याज की दर को घटाकर १६ प्रतिशत कर दिया गया है।
3. ऋण के लिए आवेदन पत्र सरल किए गए हैं।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को क्रेडिट खातों को अलग-अलग करने के लिए एसएसआई इकाइयों और चार महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहने वालों का बकाया दिखाने का निर्देश दिया है।

लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO):

लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) लघु उद्योगों के विकास के लिए नीति निर्धारण, समन्वय और निगरानी एजेंसी के लिए गठित शीर्ष स्तर का संगठन है। यह सरकार, वित्तीय संस्थानों और अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है जो छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के प्रचार और विकास में शामिल हैं।

लघु उद्योग के विकास आयुक्त लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) के प्रमुख हैं। विकास आयुक्त को विभिन्न औद्योगिक सलाहकारों और निदेशकों द्वारा प्रशिक्षण और प्रबंधन परामर्श, आर्थिक जांच और सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम को विकसित करने और लागू करने में सहायता की जाती है, विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों का विकास, औद्योगिक संपदा, लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण, विकास पिछड़े क्षेत्रों के आदि।

SIDO 27 कार्यालयों, 31 लघु उद्योग सेवा संस्थानों (SISI), 37 एक्सटेंशन केंद्रों, 6 उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास केंद्रों, 4 उत्पादन-सह-परीक्षण केंद्रों और 4 क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है।[3]

SIDO उन सभी लघु-उद्योगों को शामिल करता है, जो विशेष बोर्डों और एजेंसियों जैसे KVIC, कॉयर बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड आदि में आते हैं, सिडो के मुख्य कार्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - समन्वय, औद्योगिक विकास और विस्तार सेवाएं।

प्रत्येक श्रेणी में इसके द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

समन्वय से संबंधित कार्य:

SIDO के मुख्य समन्वय कार्यों में शामिल हैं:

1. लघु उद्योगों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास;
2. राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय;
3. संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, आदि के साथ संपर्क बनाए रखना; तथा
4. औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिए कार्यक्रम का समन्वय।

औद्योगिक विकास से संबंधित कार्य:

SIDO औद्योगिक विकास से संबंधित निम्नलिखित मुख्य कार्य करता है:

1. लघु-उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं को सुरक्षित करना;
2. छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए स्वदेशी और आयातित कच्चे माल और घटकों की आवश्यकताओं का आकलन करना और उनकी आपूर्ति की व्यवस्था करना;
3. उपभोक्ता वस्तुओं पर डेटा एकत्र करना जो आयातित हैं और उन्हें समन्वित सहायता प्रदान करके नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
4. भावी उद्यमियों के लिए मॉडल स्कीम, परियोजना रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साहित्य तैयार करना;
5. सहायक संस्थाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करना; तथा
6. सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना।[4]

एक्सटेंशन सेवाओं से संबंधित कार्य:

SIDO की मुख्य एक्सटेंशन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बेहतर तकनीकी प्रक्रिया, उत्पादन योजना, मशीनरी का चयन, कारखाने के लेआउट और डिजाइन की तैयारी, आदि के लिए तकनीकी सेवाओं का प्रावधान।
2. छोटे स्तर के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए परामर्श और प्रशिक्षण का प्रावधान;
3. छोटे उद्योगों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए विपणन सहायता का प्रावधान; तथा
4. लघु-स्तरीय इकाइयों के लिए आर्थिक जाँच और सूचना सेवाओं का प्रावधान।

SIDO का नाम बदलकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन कर दिया गया है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC):

एनआईएससी की स्थापना 1955 में एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में लगा हुआ है। इस उद्देश्य के लिए, टेक्नोक्रेट, शारीरिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी विशेष योजनाएं हैं।

NSIC के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

1. भाड़े की खरीद के आधार पर मशीनरी की आपूर्ति करना;
2. लघु-स्तरीय इकाइयों के लिए सरकारी आदेशों को सिद्ध करना;
3. बड़े उद्योगों को सहायक इकाइयों के रूप में लघु-स्तरीय इकाइयाँ विकसित करना;[5]
4. लघु-स्तरीय इकाइयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना और निर्यात को बढ़ावा देना;
5. छोटे पैमाने के क्षेत्र में वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बीच दुर्लभ कच्चे माल, घटकों और भागों का आयात और वितरण;
6. प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मशीनरी और उपकरणों का प्रोटोटाइप विकसित करना और जानना- वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कैसे;
7. औद्योगिक सम्पदा के निर्माण का उपक्रम;
8. प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से चयनित ट्रेडों और प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करना;
9. विशेष रूप से कचरे पर आधारित परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और उन्नयन; तथा
10. टर्नकी आधार पर लघु-स्तरीय परियोजनाएँ स्थापित करने में विकासशील देशों के साथ सहयोग करना।[6]

MSMEs के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल:
NSIC ने MSME के लिए विशेष रूप से एक ई-कॉमर्स पोर्टल की स्थापना की है। यह साइट एक ऐसा मंच प्रदान करेगी, जिस पर एमएसएमई अपने उत्पादों की रेंज प्रदर्शित कर सकते हैं, ब्रांड प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं और विदेशों में अपने समकक्षों के साथ नजदीकी सौदे कर सकते हैं। उद्यमियों को बाजार की जानकारी प्राप्त करने और निविदाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पोर्टल बी 2 बी और बी 2 सी सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें कॉल सेंटर समर्थन और व्यापार सहायता होगी। इसमें ऑनलाइन राष्ट्रीय और वैश्विक निविदा नोटिस और अलर्ट होंगे।

विचार-विमर्श

लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISIS):
लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISI) की स्थापना छोटे उद्यमियों को परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है - दोनों मौजूदा और भावी। SISI की गतिविधियों को DCSSI के कार्यालय के औद्योगिक प्रबंधन प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा समन्वित किया जाता है। देश भर में राज्य की राजधानी और अन्य स्थानों पर 28 SISI और 30 शाखा SISI स्थापित हैं।[7]

SISI के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
1. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इंटरफेस के रूप में सेवा करने के लिए।
2. तकनीकी सहायता सेवाओं को प्रस्तुत करना।
3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करना।
4. प्रचार कार्यक्रम आरंभ करना।

SISI भी निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है:
1. आर्थिक परामर्श / सूचना / ईडीपी परामर्श।
2. व्यापार और बाजार की जानकारी।
3. प्रोजेक्ट प्रोफाइल।
4. राज्य औद्योगिक संभावित सर्वेक्षण।
5. जिला औद्योगिक संभावित सर्वेक्षण।
6. आधुनिकीकरण और प्रत्यारोपण अध्ययन।
7. कार्यशाला की सुविधाएँ।
8. विभिन्न व्यापार / गतिविधियों में प्रशिक्षण।

विशिष्ट संस्थान:
उपरोक्त एजेंसियों के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट एजेंसियां स्थापित की गई हैं:
(मैं) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद:
यह 1968 में छोटे पैमाने की इकाइयों के तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था और उपकरण, जिग्स, जुड़नार, मर और मोल्ड के निर्माण के लिए।

1. इसके अन्य कार्य निम्नानुसार हैं:
A. उपकरण के डिजाइन और विकास में सहायता सहित परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना;[8]
B. उपकरण, और टूलींग तत्वों, जिग्स, जुड़नार, मर जाता है, आदि के घटकों को मानकीकृत करने के उपायों की सिफारिश करना; तथा
C. सीमित आधार पर मर, जिग्स, जुड़नार, गेज, आदि की टूल रूम सुविधा और उत्पादन की पेशकश।

2. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर:
यह हाथ उपकरण उद्योग के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, डिजाइन और परीक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

3. केंद्रीय उपकरण कक्ष प्रशिक्षण केंद्र:
ये नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और लुधियाना में स्थित हैं। ये डिज़ाइन, निर्माण और प्रशिक्षण में टूल रूम सेवाएं प्रदान करते हैं।

4. इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स (IDEM), मुंबई:
यह 1969 में यूएनडीआर की सहायता से स्थापित किया गया था। यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन और विकास, अंशांकन और परीक्षण, उपकरण डिजाइनिंग और निर्माण, प्रोटोटाइप निर्माण और प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी परामर्श प्रदान करता है।

5. राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (NISIET), हैदराबाद:
यह 1956 में स्थापित किया गया था। यह छोटे पैमाने के उद्योगों के उद्यमियों और कर्मचारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन में पाठ्यक्रम चलाता है।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
A. छोटे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
B. लघु उद्योगों के विकास के संबंध में शोध कार्यक्रम; तथा
C. लघु उद्योगों के विकास के लिए सेवाओं के प्रावधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय या अन्य संगठनों के साथ तकनीकी सहायता समझौतों में प्रवेश करना।

अन्य राष्ट्रीय संस्थान हैं:
6. सेंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु।
7. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टूल्स, चेन्नई।
8. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्जिंग टेक्नोलॉजी, रांची।
9. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल।
10. स्पोर्ट्स गुड्स एंड लीज़र टाइम इक्विपमेंट इंस्टिट्यूट, मेरठ।

उद्योग निदेशालय:
भारत के संविधान के तहत, लघु उद्योगों का संवर्धन और विकास एक राज्य का विषय है। इसलिए, सहायता की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य में उद्योग निदेशालय के साथ रहती है। यह SIDO और संबंधित केंद्रीय संस्थानों के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। यह विनियामक और विकासात्मक दोनों कार्य करता है। यह जिला उद्योग कार्यालयों, उद्योगों कार्यालयों और विस्तार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः जिला, उप-विभाजन और ब्लॉक स्तरों पर कार्य करता है।[9]

उद्योग निदेशालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

1. लघु-स्तरीय इकाइयों का पंजीकरण।
2. उद्योगों को वित्तीय सहायता और राज्य सहायता प्रदान करना।
3. औद्योगिक इकाइयों को दुर्लभ और स्वदेशी कच्चे माल वितरित करना।
4. कच्चे माल के आयात के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करना।
5. औद्योगिक सम्पदा और औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करना।
6. उद्यमियों को तकनीकी परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना।
8. औद्योगिक सर्वेक्षण और सूचना एकत्र करना।
9. उद्योगों के लिए रियायतें और प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।
10. गाँव और छोटे स्तर के उद्योगों का समग्र प्रशासन।
11. औद्योगिक विकास के लिए अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना।

राज्य लघु उद्योग विकास निगम (SSIDCs):

इन्हें संबंधित राज्यों में गांव और लघु उद्योगों की प्राथमिक विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।

SSIDCs के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

1. दुर्लभ कच्चे माल की खरीद और वितरण।
2. भाड़े-क्रय आधार / प्रणाली पर मशीनरी की आपूर्ति।
3. लघु-स्तरीय इकाइयों के उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करना।
4. औद्योगिक संपदा और उनके रखरखाव का निर्माण।
5. राज्य सरकार की ओर से बीज पूंजी सहायता का विस्तार करना।
6. छोटे स्तर के क्षेत्र के लिए संयुक्त उद्यमों और व्यापार केंद्रों को बढ़ावा देना।
7. प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना।[10]

औद्योगिक संपदा:

विकासशील देशों को अपने तेजी से औद्योगिकीकरण और संतुलित विकास के लिए संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक संस्थागत उपाय है औद्योगिक सम्पदा। 'औद्योगिक संपदा' शब्द को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक शहर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आदि।

एक औद्योगिक संपत्ति को "आयोजन, आवास और सर्विसिंग उद्योग, मानक उद्यमों की पेशकश करने वाले औद्योगिक उद्यमों की योजनाबद्ध क्लस्टरिंग की मांग की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है और मांग और अग्रिमों के लिए सेवाओं और सुविधाओं की एक किस्म में खड़ा किया गया है।"

डॉ। पीसी के अनुसार। अलेक्जेंडर "एक औद्योगिक संपत्ति पानी, परिवहन, बिजली, भाप, बैंकों, डाकघर, कैंटीन, घड़ी और वार्ड की सुविधाओं के साथ उपयुक्त स्थलों में आर्थिक पैमाने पर निर्मित कारखानों का एक समूह है और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए विशेष व्यवस्था के साथ प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा और सामान्य सेवा सुविधाएं। " ब्रेडो के शब्दों में, "एक औद्योगिक संपत्ति भूमि का एक पथ है जो औद्योगिक उद्यमों के एक समुदाय के उपयोग के लिए एक व्यापक योजना के अनुसार उप-विभाजित और विकसित है।"

परिणाम

एक औद्योगिक संपदा क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. यह भूमि के एक हिस्से को उपविभाजित और कारखाने के भूखंड या शेड में विकसित किया गया है।
2. यह रहने वालों को पानी, बिजली, परिवहन, उपकरण कक्ष, प्रशिक्षण, बैंक, डाकघर, मरम्मत और रखरखाव इत्यादि जैसी कई सामान्य सुविधाएं या ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है।
3. यह औद्योगिक इकाइयों की एक नियोजित क्लस्टरिंग है।
4. यह औद्योगीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास के एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया है।
5. इसे शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है।
6. यह बड़ा, मध्यम और छोटा हो सकता है।
7. इसे सरकार या सहकारी समितियों द्वारा या निजी एजेंसियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है।[7]

औद्योगिक संपदा के प्रकार:

औद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. सामान्य उद्देश्य या समग्र औद्योगिक संपदा - इस तरह की औद्योगिक संपत्ति सभी प्रकार के लघु उद्योगों को आवास प्रदान करती है। इसमें विभिन्न प्रकार की और औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं। भारत में अधिकांश औद्योगिक राज्य इस प्रकार के हैं।
2. विशेष प्रयोजन औद्योगिक संपदा - इस प्रकार की औद्योगिक संपत्ति विशेष रूप से उद्यमियों के निर्दिष्ट समूहों के लिए बनाई गई है, उदाहरण के लिए, तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति, शिल्पकार या कारीगर, आदि। उदाहरण के लिए, कारीगरों और तकनीकी कर्मियों के लिए औद्योगिक संपदा हैदराबाद में स्थापित की गई है।
3. सहायक औद्योगिक संपदा - ऐसी औद्योगिक संपदा निर्माण इकाइयों का निर्माण करती है, जो एक बड़ी औद्योगिक इकाई के लिए भागों और घटकों का उत्पादन करती हैं। यह आमतौर पर मूल इकाई के पास स्थापित किया जाता है।
4. फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट - इस प्रकार की इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक ही उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं। चमड़े के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल के सामान,

खाद्य संरक्षण, चीनी मिट्टी की चीज़ें, आदि के लिए इस तरह के एस्टेट स्थापित किए गए हैं।

5. चपटा फैक्ट्री एस्टेट्स - बड़े शहरों में निर्मित बहुमंजिला इमारतें हैं, जो सरल मशीन टूल्स की मदद से हल्के वजन के सामान बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्थान प्रदान करती हैं। वे अंतरिक्ष के संरक्षण में मदद करते हैं।

औद्योगिक संपदा के लाभ:

औद्योगिक सम्पदा निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं:

1. स्केल की अर्थव्यवस्थाएं:

एक बड़े क्षेत्र के भीतर कई मध्यम या छोटे पौधों का स्थान कई अर्थव्यवस्थाओं को प्रदान करता है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि सभी औद्योगिक इकाइयाँ सामान्य बुनियादी सुविधाओं का आनंद लेती हैं। जैसा कि एक औद्योगिक संपत्ति का आकार प्रत्येक सुविधा में गिरावट के प्रति यूनिट विकास और प्रशासन की लागत में वृद्धि करता है।

2. एग्लोमरेशन की अर्थव्यवस्थाएं:

एक औद्योगिक संपत्ति में, कई औद्योगिक इकाइयां एक साथ क्लस्टर की जाती हैं। वे परस्पर और अन्योन्याश्रित हो जाते हैं। यह उन्हें ढेर और बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के लाभों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। इन बाहरी अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर परिवहन सुविधाओं तक पहुंच, प्रशिक्षित श्रम की उपलब्धता, बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति, परीक्षण और मरम्मत की सुविधाओं तक आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता आदि शामिल हैं।[8]

3. कम निवेश:

एक छोटे पैमाने पर उद्यमी एक औद्योगिक भूखंड प्राप्त कर सकता है या किराए या किराया-खरीद के आधार पर बहा सकता है। यह निश्चित पूंजीगत आवश्यकता और साथ ही निश्चित लागत को कम करता है।

4. कम जोखिम:

औद्योगिक सम्पदा कम पूंजी निवेश और सामान्य सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के कारण जोखिम को अवशोषित करने वाले उपकरण के रूप में काम करती है।

5. समय और प्रयास की बचत:

एक व्यक्ति-उद्यमी को उपयुक्त स्थान की खोज की परेशानी से राहत मिलती है। उसे भूमि प्राप्त करने, स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने, बिजली कनेक्शन हासिल करने आदि में शामिल औपचारिकताओं में अपना समय और प्रयास बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।

6. नए उद्यमियों के लिए नर्सरी:

औद्योगिक संपदा जोखिम को कम करती है और आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से लाभप्रदता बढ़ाती है। यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए नए उद्यमियों को प्रेरित करता है।

7. आपसी सहयोग:

औद्योगिक संपदा सहयोग और संयुक्त प्रयासों की भावना को बढ़ावा देती है। एक औद्योगिक संपत्ति में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयाँ आम समस्याओं का सामना करती हैं और सामान्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहती हैं।

8. संतुलित क्षेत्रीय विकास:

अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में संपत्ति का विकास करके, सरकार देश के विभिन्न हिस्सों के संतुलित औद्योगीकरण को सुनिश्चित कर सकती है। इससे उद्योगों का विकेंद्रीकरण भी होगा।

भारत में औद्योगिक संपदा:

भारत में लघु उद्योगों के सामने आने वाले विकलांगों में से एक उनके विनिर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ अच्छी तरह से विकसित स्थान की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने 1955 में औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया।[9]

औद्योगिक संपदाओं की योजना, विकास, निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। वे निगमों या अपनी पसंद की किसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से सम्पदा चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस तरह की वित्तीय सहायता ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।

तेजी से और संतुलित आर्थिक विकास के साधन के रूप में औद्योगिक सम्पदा भारत में नियोजित विकास की योजना में प्रमुख स्थान रखती है। इन सम्पदाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा दें, एक ग्रामीण औद्योगिकीकरण और औद्योगिक स्थान के विकेंद्रीकरण में मदद करें।

इसलिए, औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिए लगातार पाँच-वर्षीय योजनाओं के तहत अधिक धनराशि आवंटित की गई है। रुपये से ऐसे आवंटन में वृद्धि हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 58 लाख रुपये से अधिक। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 90 करोड़।

उद्देश्य:

भारत में औद्योगिक संपदा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. नए उद्यमियों को सुनियोजित आवास उपलब्ध कराना।
2. लघु-स्तरीय इकाइयों को बुनियादी ढाँचा और सामान्य सुविधाएँ प्रदान करना।
3. औद्योगिक इकाइयों को एक दूसरे के उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना ताकि वे पूरक कार्य कर सकें।
4. नए और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को फैलाना।
5. लघु उद्योगों के सुचारू संचालन और विकास के लिए जन्मजात जलवायु प्रदान करना।

प्रगति:

1955 में औद्योगिक संपदाओं की योजना को अपनाने के बाद से, उल्लेखनीय प्रगति हुई है: लेकिन संपदाओं का उपयोग कम हुआ है। एक अध्ययन में 87 प्रतिशत उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय औद्योगिक सम्पदा को दिया। औद्योगिक सम्पदा में लगभग 84 प्रतिशत इकाइयाँ नई पाई गईं।

हालांकि, औद्योगिक एस्टेट स्थानीय उद्यमियों के घोंसले बन गए हैं। औद्योगिक संपदाओं के माध्यम से केवल उन्हीं इकाइयों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए जो देश के लिए अच्छी

हैं। औद्योगिक सम्पदा का उपयोग केवल छोटे स्तर की इकाइयों के लिए आवास कालोनियों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

औद्योगिक सम्पदा के अंदर काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारण थे:

1. सड़क, बिजली और पानी जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की कमी।
2. सामान्य सुविधाओं की कमी जैसे कि एक उपकरण कक्ष, गर्मी उपचार, या परीक्षण।[10]
3. संपत्ति की स्थापना से पहले यथार्थवादी सर्वेक्षण का अभाव।
4. क्षेत्र में उत्पादों की प्रासंगिकता के बारे में स्पष्ट विचार का अभाव।
5. कार्यक्रम में स्थानीय भागीदारी और सक्रिय भागीदारी का अभाव।

जिला उद्योग केंद्र (DICS):

ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर और लघु उद्योग के प्रभावी प्रचार के लिए 1978 में जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये केंद्र एक ही छत के नीचे उपलब्ध केंद्र बिंदु हैं जो छोटे पैमाने पर और गाँव के उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सभी सेवाओं और समर्थन को प्रदान करते हैं। ये औद्योगिक विकास के लिए जिला स्तर पर एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचे के रूप में काम करते हैं।

संरचना:

एक डीआईसी में तकनीकी पृष्ठभूमि वाले एक महाप्रबंधक, चार कार्यात्मक प्रबंधक और तीन परियोजना प्रबंधक होते हैं। कार्यात्मक प्रबंधक आर्थिक जांच, क्रेडिट, ग्रामोद्योग और कच्चे माल / विपणन / प्रशिक्षण आदि से संबंधित हैं। परियोजना प्रबंधक संबंधित जिले की जरूरतों के लिए प्रासंगिक क्षेत्र में तकनीकी सेवा प्रदान करते हैं।

जिला उद्योग केंद्र कुटीर, ग्रामीण और छोटे स्तर के उद्योगों के संवर्धन और विकास से संबंधित विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध और समन्वय बनाए रखते हैं। सरकार ने इन केंद्रों को आवश्यक शक्तियां सौंप दी हैं। इन केंद्रों के कामकाज की समीक्षा के लिए निगरानी और समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

कार्य और भूमिका:

डीआईसी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

1. (मैं) सर्वेक्षण:

एक डीआईसी कच्चे माल की उपलब्धता, मानव कौशल, बुनियादी ढांचे, मांग, आदि को ध्यान में रखते हुए एक जिले की औद्योगिक क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करता है। यह तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करता है, उत्पाद लाइनों की पहचान करता है और लागतों का पता लगाता है। ऐसी जांच के आधार पर, यह उद्यमियों को निवेश सलाह प्रदान करता है।[8]

2. क्रिया योजनाएँ:

जिले में बंदोबस्ती और संभावनाओं के आधार पर, एक डीआईसी औद्योगिक विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करता है। यह योजना लीड बैंक के जिला क्रेडिट योजना के साथ समन्वित है।

3. मूल्यांकन:

एक DIC उद्यमियों से प्राप्त विभिन्न निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है। फिर यह विभिन्न क्रेडिट योजनाओं की व्याख्या करके, आवेदन पत्र तैयार करने, आवेदनों के आकलन में मदद करने, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क बनाए रखने और जिले में औद्योगिक ऋण के प्रवाह की निगरानी करके योग्य उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मदद करता है।

4. दिशा निर्देश:

एक डीआईसी गाइड और उपयुक्त मशीनरी और उपकरणों की पहचान करने में उद्यमियों की सहायता करता है, मशीनरी और उपकरणों के स्रोतों का पता लगाने, योजना के आदेशों में मदद करने, मशीनरी आयात करने में मदद करता है, आदि यह कच्चे माल की आवश्यकताओं और उनके स्रोतों का भी पता लगाता है, कच्चे माल की थोक खरीद की व्यवस्था करता है और बातचीत करता है दुर्लभ और महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विभिन्न अधिकारियों के साथ।

5. विपणन सहायता:

इस समारोह के तहत, एक डीआईसी मार्केटिंग जानकारी एकत्र करता है, मार्केटिंग आउटलेट्स का आयोजन करता है, सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखता है, अनुषंगीकरण और निर्यात की संभावनाओं का आकलन करता है, और उद्यमियों को उचित विपणन रणनीतियों का सुझाव देता है।

6. आर एंड डी संस्थानों के साथ संपर्क करें:

एक डीआईसी प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता सुधार, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि के उन्नयन के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ संबंध बनाए रखता है।

7. प्रशिक्षण:

एक DIC कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह IRD और TRYSTM प्रोग्रामर के प्रशासन में DRDA के तकनीकी हाथ के रूप में भी कार्य करता है, और प्रशिक्षुओं के लिए अवसरों और परियोजनाओं की पहचान करता है।

(ज) विशेष योजनाएँ:

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विशेष योजनाओं के लिए डीआईसी को परिचालन जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रगति:

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को सहायता प्रदान करने में डीआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने नए उद्यमियों को आकर्षित और प्रोत्साहित किया है। एसएसआई इकाइयों और ग्रामीण कारीगरों को स्थापित करने में भी इन केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओएस):

तकनीकी परामर्श संगठनों (TCOs) का एक नेटवर्क अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सत्तर और अस्सी के दशक में राज्य स्तर के वित्तीय / विकास संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर छोटे उद्योगों और नए उद्यमियों की परामर्श आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था।

वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में 15 TCO संचालित हैं, जिनमें से कुछ एक से अधिक राज्यों को कवर करते हैं।[9]

कार्य:

प्रारंभ में, TCO के कार्य छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए पूर्व-निवेश अध्ययन पर केंद्रित थे।

इन वर्षों में, उन्होंने निम्नलिखित को शामिल करने के लिए अपने कार्यों में विविधता लाई है:

A. प्रोजेक्ट प्रोफाइल और व्यवहार्यता प्रोफाइल तैयार करना।
B. औद्योगिक संभावित सर्वेक्षण करने के लिए।
C. संभावित उद्यमियों की पहचान करना और उन्हें तकनीकी और प्रबंधन सहायता प्रदान करना।
D. विशिष्ट उत्पादों के लिए बाजार अनुसंधान और सर्वेक्षण करना।
E. परियोजना की देखरेख और जहां आवश्यक हो, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
F. आधुनिक तकनीक पर आधारित निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए निर्यात परामर्श शुरू करना।
G. उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करना।
H. व्यापारी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए।
I. पिछले दो वर्षों के दौरान TCOs की प्रगति / प्रदर्शन का सारांश दृश्य।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड):

भारत सरकार ने देश में आठ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। एक एसईजेड विशेष रूप से सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ शुल्क मुक्त एन्क्लेव है। एसईजेड में स्थापित इकाइयों को आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी इकाइयों को कई अन्य प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

एसईजेड पर सरकार की नीति उन राज्यों में उद्योगों को आकर्षित करने में मदद करेगी जहां ऐसे क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी एसईजेड स्थापित करने की अनुमति है। एसईजेड पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने में मदद करेगा क्योंकि अधिकांश एसईजेड ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं।

एसईजेड, 202 का निर्माण करने का अधिकार रखने वाली 583 कंपनियों की सेज स्कीम बहुत ही ज्यादा लुप्त हो चुकी है। स्वीकृतियां गिर रही हैं और निकासी बढ़ रही है।[10]

इस सब के पीछे चार मुख्य कारण हैं:

1. 2008 में भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी सरकार से डेवलपर्स को हस्तांतरित की गई, जिन्हें भूमि प्राप्त करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
2. प्रत्यक्ष कर संहिता का मसौदा मुनाफे से निवेश तक प्रोत्साहन के आधार को बदलता है।
3. एसईजेड को स्थानांतरित करने के लिए निर्यात इकाइयों के लिए प्रोत्साहन कम हो रहे हैं।
4. बजट 2011 आयकर छूट को हटाता है, एसईजेड नीति पर 15 वर्ष के कार्यकाल के वादे को तोड़ते हुए 18.5% न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) और 15% लाभांश वितरण कर को समाप्त करता है।

कुछ क्षेत्रों में और कुछ राज्य राज्यों में सेज़ की बड़ी हिस्सेदारी है।

एंजेल इन्वेस्टर्स एंड मेंटरहै:

धन से अधिक, यह सही सलाह है जो एक नए के लिए सफलता और विफलता के बीच के अंतर को जादू कर सकती है उद्यम। एंजेल निवेशक और संरक्षक नए उपक्रमों के संस्थापकों की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, राजन आनंदन ने 6 वर्षों में 20 स्टार्ट-अप में निवेश किया है और कई स्टार्ट-अप को कोचिंग दी है। स्टार्ट-अप वेंचर के लिए सही मात्रा में और सही समय पर पैसे का एक्सेस महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार ने एकल पृष्ठ पंजीकरण शुरू किया जिसे उद्योग आधार ज्ञापन कहा जाता है। पिछले पंजीकरण फॉर्म में 14 पृष्ठ शामिल थे। MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) को रु। तक की गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं को वित्तपोषित करने के लिए शुरू किया गया था। प्रत्येक को 10 लाख। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) रुपये के कार्पस के साथ बनाया गया था। ग्रीनफील्ड / ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को वित्त करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये।

भारत में लघु उद्योग को संस्थागत समर्थन - 14 संस्थान जो लघु उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं

अनुगामी वे संस्थान हैं जो छोटे उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं:

1. वाणिज्यिक बैंक
2. राज्य के वित्तीय निगम
3. जिला उद्योग केंद्र (DIC)
4. लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISI)
5. लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI)
6. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)
8. लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO)
9. लघु उद्योग बोर्ड (SSIB)
10. उद्यमी मार्गदर्शन ब्यूरो (EGB)[10]
11. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)
12. तकनीकी परामर्श संगठन (TCO)
13. लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (SIETI)
14. लघु उद्योग विकास निगम (सिडको)

1. जिला उद्योग केंद्र (DIC):

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अतीत में छोटे और गाँव के उद्योगों के विकास के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन वास्तविक उपलब्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है, क्योंकि औद्योगिक विकास

के लिए ध्यान मुख्य रूप से बड़े शहरों और राज्यों पर था। राजधानियों।

साथ ही छोटे उद्योगों और जटिल प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास में शामिल संस्थानों की बहुलता ने औद्योगिक इकाइयों को छोटे उद्यमियों के लिए एक कठिन कार्य को बढ़ावा देने का काम किया।

इसलिए, एक ऐसी विकास एजेंसी स्थापित करना आवश्यक समझा गया जो एक ही छत के नीचे गाँव और छोटे उद्योगों को सभी सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान कर सके। तदनुसार, छोटी इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 8 मई 1978 को डीआईसी की स्थापना की गई थी।[9]

प्रत्येक जिले के मुख्यालय में एक डीआईसी है। डीआईसी की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य एजेंसियों के संबंध में मुख्य समन्वयक या बहुआयामी एजेंसी के रूप में कार्य करना है। भावी लघु उद्यमी को उद्योग स्थापित करने और चलाने के लिए डीआईसी से सभी सहायता मिलेगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के महानगरीय शहरों को डीआईसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

डीआईसी के संगठनात्मक सेटअप:

आमतौर पर प्रत्येक डीआईसी में निम्नलिखित शामिल हैं:

मैं। प्रमुख के रूप में संयुक्त निदेशक उद्योग के रैंक के एक महाप्रबंधक।

ii। चार कार्यात्मक प्रबंधक, जिनमें से तीन आर्थिक जांच, ऋण और ग्राम उद्योगों के क्षेत्रों में होंगे। चौथे कार्यात्मक प्रबंधक को प्रत्येक जिले की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर किसी भी क्षेत्र जैसे कच्चे माल / विपणन / प्रशिक्षण आदि में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

iii। संबंधित जिले की आवश्यकताओं के लिए संबंधित क्षेत्र में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन परियोजना प्रबंधक। उनकी भूमिका छोटे क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन में सुविधा प्रदान करना है।

उप-प्रभाग स्तर पर, उद्योग और उद्योग संवर्धन अधिकारी के सहायक निदेशक हो सकते हैं, लेकिन ये पद हर राज्य में मौजूद नहीं हैं।

डीआईसी के कार्य:

डीआईसी की भूमिका मुख्य रूप से प्रचार और विकास है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इसे छोटे और गाँव के उद्योगों को आवश्यक सेवाएँ और सहायता प्रदान करनी होगी।

इसके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. मैं। उद्यमियों की पहचान - विशेषकर छोटे शहरों में जिले भर में उद्यमशीलता प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित करके डीआईसी नए उद्यमियों का विकास करता है।
2. परियोजनाओं का चयन - डीआईसी नए उद्यमियों को उनके लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन के लिए तकनीकी सलाह देता है।
3. एसएसआई के तहत पंजीकरण - डीआईसी नए उद्यमियों को अनंतिम और स्थायी पंजीकरण प्रदान करता है। परियोजनाओं के चयन के बाद, उद्यमियों को अनंतिम एसएसआई पंजीकरण के साथ जारी किया जाता है जो वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एक बार एक इकाई अस्तित्व में आती है, तो इकाई स्थायी रूप से पंजीकृत होती है।

   अनंतिम पंजीकरण पहले उदाहरण में दो साल के लिए प्रदान किया जाता है और उसके बाद, हर साल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नवीनीकृत किया जा सकता है कि पार्टी इकाई को स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, लेकिन यह नवीनीकरण केवल दो बार तक सीमित है।
4. विभिन्न विभागों से मंजूरी - यह विभिन्न विभागों से परियोजना के लिए मंजूरी पाने के लिए पहल करता है और तेजी से बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उपायों का पालन करता है।[8]
5. विभिन्न अन्य विभागों को आवेदन की सिफारिश करना - जिला उद्योग केंद्र वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एसएसआई इकाइयों के आवेदनों की सिफारिश करता है।

   डीआईसी औद्योगिक इकाइयों की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद, किराया-खरीद / पट्टे के आधार पर मशीनरी की खरीद के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को एसएसआई इकाइयों के आवेदन की भी सिफारिश करता है।
6. बीज धन की व्यवस्था करना - डीआईसी, विभिन्न संबद्ध निगमों के माध्यम से, उन उद्यमियों को बीज धन प्रदान करता है जो तकनीकी रूप से अपने छोटे औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए योग्य हैं, लेकिन वित्तीय सहायता के लिए अपने योगदान के एक हिस्से के रूप में अपनी स्वयं की पूंजी जुटा पाने की स्थिति में नहीं हैं। जो उन्हें बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करना है।
7. कच्चे माल की आपूर्ति में सहायता - डीआईसी संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए आवश्यक सिफारिशें करता है और जहां भी आवश्यक हो, कच्चे माल के आयात के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करता है। यह सुविधा SSI इकाइयों को नियंत्रित दरों पर और उनकी निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार कच्चा माल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
8. वित्तीय सहायता - उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एसएसआई इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के तहत, पात्र बेरोजगार युवकों को औद्योगिक, व्यवसाय और सेवा गतिविधियों के लिए आसान शर्तों और शर्तों पर ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
9. सब्सिडी योजनाएँ - DIC SSI इकाइयों और ग्रामीण कारीगरों को सहायता प्रदान करती है जैसे विभिन्न संस्थानों से बिजली सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, IRDP के तहत सब्सिडी आदि।[7]

DIC ऐसी SSI इकाइयों को भी सब्सिडी प्रदान करता है जो विभिन्न परीक्षण करने के लिए परीक्षण मशीनरी / उपकरण खरीदती हैं। यह एसएसआई इकाइयों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादों पर निरंतर निगरानी रखने में मदद करता है।

10. खरीद पसंद का अनुदान - DIC ने SSTP इकाइयों को 15% खरीद की वरीयता और रियायत प्राप्त करने के लिए अनुमोदित विभिन्न विभागों द्वारा उत्पादों की खरीद के संबंध में बड़ी और मध्यम इकाइयों को 5 प्रतिशत की अनुमति देता है।

11. ग्राम कारीगरों और हस्तशिल्पों को सहायता - डीआईसी गाँव के कारीगरों के लिए संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है।

12. उद्यमिता विकास कार्यक्रम / सेमिनार - उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है क्योंकि उद्यमी अत्यधिक योग्य हो सकता है, लेकिन वह अभी भी विभिन्न पहलुओं और औद्योगिक उद्यम की स्थापना के लिए आवश्यक कदमों से परिचित नहीं हो सकता है।

    जिला उद्योग केंद्र युवा उद्यमियों में उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थानों और विभिन्न तकनीकी परामर्श संगठनों के सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

13. आयात और निर्यात सहायता - प्रतिबंधित और सीमित अनुमेय श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को आयात लाइसेंस के विरुद्ध आयात किया जा सकता है। आयात लाइसेंस संबंधित डीआईसी के महाप्रबंधक की सिफारिशों पर संबंधित आयात और निर्यात अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

    निर्यात वस्तुओं के लिए इच्छुक एसएसआई इकाइयों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इस पंजीकरण के लिए आवेदन संबंधित डीआईसी के महाप्रबंधक के माध्यम से किया जाता है।

14. मेले और प्रदर्शनियाँ - भारत के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों द्वारा निर्मित किए जा रहे औद्योगिक उत्पादों को व्यापक प्रचार देने के लिए, भारत सरकार हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करती है। यह औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादों को बाहरी दुनिया में निर्यात करने, भावी खरीदारों की पहचान करने और नए विपणन रास्ते खोलने में मदद करता है।

डीआईसी अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए मुफ्त स्थान की सुविधा प्रदान करके इन मेलों में भाग लेने के लिए एसएसआई इकाइयों को प्रोत्साहित करते हैं।

इसलिए, जिला उद्योग केंद्र एक छत के नीचे उद्यमियों को पूर्व-निवेश, निवेश और निवेश के बाद की सहायता प्रदान करने वाले हैं।

2. वाणिज्यिक बैंक और उद्यमी विकास:

वाणिज्यिक बैंक विशेष रूप से सामान्य रूप से और उद्यम क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदारीकरण के युग में व्यवसाय और उद्योग के प्रचार और विकास में बैंकों की भूमिका सभी महत्वपूर्ण हो गई है।

इन दिनों, वाणिज्यिक बैंकों ने केवल छोटे उद्यमियों को वित्त के विस्तार तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उनकी प्रगति और विकास के लिए वास्तविक चिंता दिखाई है। वे अब उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र के प्रवर्तकों के रूप में उनकी नई भूमिका में, उन्होंने एक और चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया है। वे अब विशेष संस्थानों जैसे डीआईसी, एसआईएसआई, टीसीओ आदि के साथ उद्यमियों को पहचानने के लिए और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए ईडीपी पकड़ रहे हैं और नए उपक्रम शुरू करने के लिए उनकी निगरानी कर रहे हैं।[6]

1. मैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI):

भारतीय स्टेट बैंक हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। जोखिम भरे नए उद्यम लेने के लिए संभावित उद्यमियों की निगरानी के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए, एसबीआई ने 1978 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) शुरू किया। बैंक के उपक्रम के अनुसार, ईडीपी में व्यवहार विज्ञान, प्रबंधन पहलुओं में एक महीने का गहन प्रशिक्षण शामिल है। और क्षेत्र प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, बोर्डिंग और लॉजिंग की पूरी लागत बैंक द्वारा वहन की जाती है।

बैंक के EDP में तीन चरण होते हैं:

A. दीक्षा चरण - उद्यमशीलता के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए।

B. विकास चरण - प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा और प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के लिए।

C. समर्थन चरण - उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए परामर्श, प्रोत्साहन और इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल समर्थन।

बैंक ने लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता की कई योजनाएं शुरू कीं।

इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

A. उदारीकृत योजना:

1959 में, SBI ने अपनी सभी शाखाओं में लघु उद्योगों की सहायता की उदारीकृत योजना शुरू की।

अपनी उदारीकृत योजना के तहत, एसबीआई निम्नलिखित रूपों में परियोजना लागत की 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

1. कारखाना भूमि की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए सावधि ऋण।
2. नवीनीकरण, आधुनिकीकरण आदि के लिए संयंत्र और मशीनरी प्राप्त करने के लिए सावधि ऋण।[5]
3. सभी उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए नकद ऋण के आधार पर कार्यशील पूंजी।

B. उद्यमी योजना:

1967 में, SBI ने आवश्यक होने पर 100% की तकनीकी रूप से योग्य या प्रशिक्षित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्यमी योजना शुरू की। लक्ष्य समूह वे टेक्नोक्रेट्स हैं जिनके पास बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य मार्जिन को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता का अभाव है।

यहां तक कि स्टार्ट-अप अवधि के दौरान उद्यमियों की जीविका आवश्यकताओं का भी प्रावधान है। यूनिट के संचालन के पहले तीन वर्षों के लिए ब्याज की रियायती दरें इस तरह के अग्रिमों के लिए निर्धारित हैं।

C. इक्विटी फंड स्कीम (EFS):

एसबीआई ने 1978 के अंत तक अपनी इक्विटी फंड योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से इक्विटी समर्थन की आवश्यकता में नई एसएसआई इकाइयों की सहायता करना है, जो कि रु। लंबी अवधि के आधार पर एक लाख चुकाने योग्य। सहायता की वास्तविक राशि कुल परियोजना लागत के 25% और प्रमोटर के योगदान के बीच अंतर है। 5 से 7 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के दौरान ईएफएस सहायता की कोई चुकौती नहीं होती है, जिसके दौरान अन्य ऋणों का फिर से भुगतान किया जाता है। इसके बाद, इसे किश्तों के माध्यम से 5-7 साल की अवधि में चुकाया जाना है। इक्विटी फंड स्कीम के तहत दिए गए फंड पर कोई ब्याज नहीं लगता है।

2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB):

अपने मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन के माध्यम से, PNB लघु उद्योगों को सहायता के समान पैकेज प्रदान करता है।

उपायों के पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं:

A. बैंक प्रस्तावों की आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन करते हैं और तकनीकी सलाहकारों की सहायता से बाजार-सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने में मदद करते हैं।

B. बैंक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न सरकारी सहमति प्राप्त करने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है।

C. बैंक उद्यमियों को डिबेंचर, टर्म लोन, वित्तीय संस्थानों से आस्थगित भुगतान गारंटी के रूप में वित्त जुटाने में सहायता करता है।

D. बैंक संयंत्र और मशीनरी, घटकों, कच्चे माल आदि के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाने में सहायता करता है।

E. बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों के पूंजी आधार को मजबूत करने का सुझाव देता है, जो कि साझेदारी फर्मों को निजी लिमिटेड कंपनियों में परिवर्तित करने या निजी लिमिटेड कंपनियों को सार्वजनिक सीमित कंपनियों में परिवर्तित करने / विस्तारित करने का इरादा रखता है।[4]

अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में उद्यमिता सेवा प्रकोष्ठ हैं जो किसी परियोजना की पहचान से लेकर उसके कार्यान्वयन और विपणन तक उद्यमियों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।

3. राज्य के वित्तीय निगम:

1951 में पारित संसद के SFCs अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों में राज्य वित्तीय निगम स्थापित किए गए हैं। ये निगम लघु और मध्यम-उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। नए के साथ-साथ मौजूदा उद्योगों को ऋण दिया जाता है।

इन निगमों की महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

A. फाइनेंसिंग योजनाएं:

1. समग्र ऋण योजना - रु। स्थानीय और उपलब्ध कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़े गांवों और छोटे शहरों के कारीगरों को बिना किसी मार्जिन मनी के 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
2. तकनीकी उद्यमियों के लिए योजना - निगमों में इंजीनियरिंग के किसी भी विषय में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले तकनीकी कर्मियों द्वारा पदोन्नत औद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण की योजना है। योजना के तहत अधिकतम सीमा रुपये की है। 151 लाख 1 टी के मार्जिन मनी के साथ 2 लाख।
3. टिनी यूनिट योजना - निगम छोटी इकाइयों को सहायता प्रदान करते हैं जो संयंत्र और मशीनरी को रु। के मूल्य तक प्राप्त करते हैं। अचल संपत्तियों पर 20% के मार्जिन पर 2 लाख।
4. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना - निगम रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता का विस्तार करते हैं। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 3 लाख (40% orthopaedically विकलांग) व्यक्तियों को औद्योगिक इकाइयों के रूप में स्थापित करने के लिए कम से कम 60% शेयर के साथ एकमात्र मालिकाना / साझेदारी चिंताओं।
5. भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजना - निगम पूर्व सैनिकों (पूर्व सैनिकों की विधवाओं सहित) को वित्तीय सहायता देते हैं और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक (पुन: बंदोबस्त) द्वारा प्रायोजित विकलांग सेवा कर्मी होते हैं। योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा रु। 11.25 लाख और न्यूनतम प्रमोटर का योगदान 10% है।[3]
6. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए योजना - निगम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा निल मार्जिन मनी पर रु। 50,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के लिए ब्याज की रियायती दर पर।
7. महिला उद्यमियों के लिए योजना - निगम महिला उद्यमियों द्वारा पदोन्नत और प्रबंधित एसएसआई इकाइयों (कुटीर, गाँव और छोटे उद्योगों सहित) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। योजना के तहत प्रमोटर का योगदान परियोजना लागत का 15% है।
8. एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए प्रोत्साहन - वे औद्योगिक चिंताएँ जो 1.4.1987 को या उसके बाद के ऋणों को स्वीकृत की गईं, उन वर्षों में ब्याज पर 20% की छूट के लिए हकदार होंगी, जिसमें उनकी निर्यात बिक्री कुल बिक्री के 25,2001T तक पहुँचती है या उससे अधिक है। इस छूट के अलावा, 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ भी निर्माण अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक नहीं होने पर भी छूट की हकदार होंगी।

B. प्रोमोशनल योजनाएं:

1. (मैं) विशेष पूंजी योजना:

विशेष पूंजी योजना के तहत, इक्विटी के रूप में सॉफ्ट लोन सहायता परियोजना की लागत या रुपये की 20% तक प्रदान की जाती है। 4 लाख, जो भी कम हो, ऐसे उद्यमियों के लिए जो तकनीकी रूप से योग्य हैं या अन्यथा निर्धारित न्यूनतम प्रवर्तक के योगदान और वास्तव में उपलब्ध धन के बीच अंतर को भरने के लिए लाइन में अनुभव के अधिकारी हैं। इसे प्रमोटर के योगदान के रूप में माना जाता है। ब्याज के भुगतान के लिए 3 साल की मोहलत दी गई है।

2. बीज पूंजी सहायता:

इस योजना के तहत बीज पूंजी की मंजूरी, संवितरण और वसूली के लिए निगम लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस योजना के तहत परियोजना की लागत की 10% रुपये की सीमा तक सहायता दी जाती है। 15 लाख रुपये तक की लागत वाली इकाइयों को 15 लाख रु। 5 करोड़ रु।

इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र उद्यमी तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी हैं या उनके पास पेशेवर योग्यता है, लेकिन नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए या मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए धन की कमी है या छोटे स्तर के सेक्टर से मध्यम स्तर के क्षेत्र के लिए विविधीकरण और स्नातक हैं बंद इकाई को प्राप्त करना और शुरू करना। यह सहायता न्यूनतम प्रमोटर के आवश्यक योगदान और वास्तव में उपलब्ध निधियों के बीच अंतर को भरने के लिए दी गई है।[2]

3. ब्रिजिंग ऋण योजना:

निगम उन मामलों में प्रतिबंधात्मक आधार पर ऋण सुविधाओं को बढ़ाते हैं, जहां निगमों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन नियमों और शर्तों का अनुपालन उनके नियंत्रण से परे कारणों के कारण पहली बार में नहीं किया जा सकता है।

4. आधुनिकीकरण योजना:

अधिकांश निगमों में मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए एक योजना है जिसमें निर्यात अभिविन्यास, आयात प्रतिस्थापन, ऊर्जा की बचत, सामान्य मार्जिन पर क्षमता उपयोग में सुधार (न्यूनतम प्रवर्तक का योगदान 10% होना चाहिए)।

5. उपकरण पुनर्वित्त योजना:

निगम 22.5% मार्जिन पर पूंजीगत सामान / उपकरण (आयातित / स्वदेशी) प्राप्त करने के लिए मौजूदा, अच्छी तरह से चलने वाली इकाइयों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पात्र होने के लिए, चिंता 4 साल (ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए, दो साल की न्यूनतम अवधि के लिए) के संचालन में होनी चाहिए थी और दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करना चाहिए था और संस्थानों / बैंकों के साथ डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

6. बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए योजना:

निगम संभावित बीमार इकाइयों को राहत और रियायतें प्रदान करते हैं। आईडीबीआई की पुनर्वित्त योजना और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, राहत और रियायतें जैसे अतिदेय ब्याज की धनराशि, दंड ब्याज की छूट, ऋण का पुनर्निर्धारण, अतिरिक्त ऋण के लिए मार्जिन राशि आदि प्रदान की जाती हैं। अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यदि आवश्यक हो, आवश्यक अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना के लिए भी अनुमति है।

योजना की प्रकृति, विभिन्न नियम और कानून जैसे पात्रता की स्थिति, ऋण की अधिकतम सीमा, ब्याज की दर, प्रमोटर का योगदान समय-समय पर बदलते रहते हैं। स्थानीय स्थितियों और समय की आवश्यकता के आधार पर एक राज्य वित्तीय निगम की नीतियों में दूसरे से कुछ बदलाव हो सकते हैं। उपर्युक्त योजनाएँ वित्तीय निगमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए सरकार की नीतियों का एक सामान्य व्यापक विचार हैं।[1]

4. लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISI):

लघु उद्योग की सफलता काफी हद तक अच्छी तरह से स्थापित संस्थागत सेट-अप पर निर्भर करती है। देश में तेजी से फैल रहे एसएसआई क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सरकार ने पर्याप्त संस्थागत सहायता का सृजन किया है। 1956 में स्थापित, लघु उद्योग सेवा संस्थान - प्रत्येक राज्य में एक ने लघु उद्योगों को बहुत उपयोगी सेवाएं प्रदान की हैं।

SISIs का प्रशासनिक सेटअप:

लघु उद्योग सेवा संस्थान (SISI) एक बहुउद्देशीय संस्था है। यह एसएसआई और सरकारी विभागों, अर्ध-सार्वजनिक संस्थानों और अन्य एजेंसियों को बड़े पैमाने पर एक सलाहकार निकाय है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोटे स्तर के क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय संविधान के तहत, केंद्र सरकार के समग्र मार्गदर्शन और सहायता के तहत राज्य सरकारें SSI क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने, उद्योगों के लिए सहायता अधिनियम के तहत ऋण वितरित करने, राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना, एक्सटेंशन सेवाएँ प्रदान करने, दुर्लभ कच्चे माल के वितरण और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उनके राज्य के समकक्षों के साथ SISI का सहयोग और समन्वय उनके सफल संचालन के लिए आवश्यक है। SISI निदेशक सामान्य रूप से SSI के विकास के लिए राज्य द्वारा गठित सभी सलाहकार समितियों का सदस्य होता है। विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक विस्तार केंद्र SISI से संबद्ध हैं और SISI के निदेशकों द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। जबकि SISI सभी प्रकार के छोटे उद्योगों को पूरा करता है, लेकिन विस्तार केंद्र केवल एक या दो प्रकार के उद्योगों में कार्य करता है।

SISI में आमतौर पर निम्नलिखित विभाजन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक उप निदेशक या सहायक निदेशक के नेतृत्व में होता है, जैसा कि मामला हो सकता है:

1. मैं। खातों सहित प्रशासन
2. आर्थिक जाँच
3. औद्योगिक प्रबंधन और प्रशिक्षण
4. औद्योगिक डिजाइन
5. यांत्रिक

6. इलेक्ट्रोनिक्स सहित विद्युत
7. उस विशेष अवस्था में धातु रसायन, चमड़ा, चीनी मिट्टी और कांच जैसे उद्योग के प्रकार के आधार पर कोई अन्य विभाजन।

एक प्रभाग में अधिकारियों की ताकत उस राज्य में उद्योगों की एकाग्रता पर निर्भर करती है।[2]

एसआईएसआई के कार्य:

SISI के कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

A. तकनीकी परामर्श और सलाहकार सेवा:

चूंकि SISI सलाहकार निकाय हैं, इसलिए वे उद्यमियों को केंद्र / राज्य सरकारों और तकनीकी सलाहकार सेवाओं के लिए नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि SISI सलाहकार निकाय हैं, उनकी सलाह केंद्र या राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है

सलाहकार सेवाएं लाभदायक लघु उद्यमों के चयन, उपयुक्त मशीनरी और उपकरणों की पसंद, कच्चे माल के निर्माण प्रसंस्करण की तकनीक का मूल्यांकन, लघु उद्योगों के उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण के मान्यताप्राप्त मानकों को अपनाने से संबंधित है, जो आपूर्ति के लिए छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करती हैं। सरकारों के स्टोर खरीद कार्यक्रम में भाग लें। संस्थान बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए भागों / घटकों की आपूर्ति करने के लिए छोटे पैमाने पर इकाइयां स्थापित करने की संभावना की खोज करता है।

B. प्रशिक्षण सुविधाएं:

इस संस्थान और इसके विस्तार केंद्रों से जुड़ी कार्यशालाओं में बुनियादी ट्रेडों में श्रमिकों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

छोटे उद्योगपतियों के लाभ के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।[3]

विभिन्न प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रबंधन की सराहना
2. उत्पादन, योजना और प्रबंधन
3. निर्यात विपणन सहित विपणन
4. वित्तीय प्रबंधन और लागत नियंत्रण
5. पर्यवेक्षी विकास
6. कार्य अध्ययन।

निष्कर्ष

लघु उद्योगों के व्यावहारिक पहलुओं पर जोर देने के साथ युवा इंजीनियरों के लिए लघु उद्योग उद्यमिता और प्रबंधन में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यह योग्य उद्यमियों का एक नया वर्ग बनाने में सहायक रहा है।

प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रतिभागियों को बड़े और छोटे उद्योगों और वास्तविक प्रबंधन समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा की जाती है। कुछ उद्यमियों को विदेशों में अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है।

C. सामान्य सुविधा सेवाएं:

भारत के अधिकांश SISI में कार्यशालाएँ, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय हैं।

इन कार्यशालाओं की मदद से, SISI निम्नलिखित गतिविधियाँ करते हैं:

1. चयनित मशीनों और उपकरणों पर आधुनिक तकनीकी प्रक्रियाओं के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए।[9]
2. छोटे पैमाने के उद्योगों के कच्चे माल और उत्पादों के परीक्षण में सहायता करना और उनके निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता करना।
3. सामान्य सेवाएं और टूल रूम सुविधाएं प्रदान करना।
4. नए और स्थानापन्न कच्चे माल पर प्रयोगों और प्रयोगशाला विश्लेषण को अंजाम देने के लिए और छोटे उद्यमों द्वारा सामना किए गए प्रदर्शन, गुणवत्ता में सुधार और ऐसे अन्य क्षेत्र की समस्याओं पर डिजाइन चर के प्रभावों का अध्ययन करें।

D. विपणन सहायता:

विशिष्ट उत्पादों के लिए बाजार की प्रकृति और सीमा पर आर्थिक जानकारी एकत्र की जाती है और उनके अनुरोध पर छोटे उद्योगपतियों को दी जाती है। संस्थान विदेशी बाजारों में निर्यात प्रक्रियाओं और रुझानों पर परामर्श द्वारा निर्यात संवर्धन सेवा प्रदान करता है।

लघु उद्योगों के विशिष्ट उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण भी क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है ताकि क्षेत्र में अपने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सके।

E. SSI के लिए वित्त व्यवस्था की व्यवस्था करना:

आमतौर पर, लघु-स्तरीय उद्योगों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि उनके पास ऋण योग्यता की कमी होती है, लेकिन SISI वित्तीय संस्थानों के साथ एक सलाहकार और समन्वयकारी एजेंसी के रूप में काम करती है और भावी उधारकर्ताओं के उत्पादों की विपणन क्षमता और गुणवत्ता पर उनकी रिपोर्ट करती है। राज्य वित्तीय निगम भी लघु इकाइयों को ऋण देते समय SISI से परामर्श करते हैं।

F. निर्यात संवर्धन:

स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) मुख्य रूप से निर्यात और आयात के लिए जिम्मेदार है। छोटे पैमाने के क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका एक अलग प्रभाग है। SISI इसके लिए उपयुक्त छोटी इकाइयों को निर्धारित करने के लिए सहयोग करते हैं जो निर्यात के लिए निर्माण कर सकते हैं और वे उन्हें प्रशिक्षण, उत्पादों के निरीक्षण और अन्य माध्यमों से मदद करते हैं।

G. सहायक विकास:

भारत सरकार ने माना है कि बड़े पैमाने पर और लघु उद्योगों का विकास जहाँ तक संभव हो पूरक होना चाहिए। छोटे निर्माताओं को बड़े निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय पूरक के उत्पादन में विशेषज्ञ होना चाहिए।

बड़े पैमाने पर और छोटे पैमाने के उद्योगपतियों को एक साथ लाने में SISI प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक संस्थान में एक अधिकारी को विशेष रूप से सहायक इकाइयों के विकास के लिए सौंपा गया है। बड़े पैमाने की इकाइयों द्वारा आवश्यक घटकों को प्रदर्शित करने वाले शो-रूम को एसआईएसआई द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।

H. उद्यमिता को बढ़ावा:

उद्यमिता के विकास के संबंध में SISI की मुख्य गतिविधियों में इंजीनियर उद्यमियों, बेरोजगार स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और विज्ञान स्नातकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन शामिल है।

SISI द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक अविकसित क्षेत्रों में गहन अभियान के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

मैं। सामान्य सेवाएं:

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़े-खरीद के आधार पर मशीनरी की खरीद पर सलाह देने के लिए।
2. राज्य व्यापार निगम की योजनाओं के लिए इकाइयों का पंजीकरण करना।
3. सरकारी भंडारों की खरीद कार्यक्रम में भागीदारी के लिए छोटे स्तर के उद्यमों को सूचीबद्ध करना।
4. राज्य सरकार की विभिन्न समितियों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।

5. लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI):

लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता का बड़ा प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अक्टूबर 1989 में संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना की। IDBI की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।

बैंक ने 2 अप्रैल, 1990 से अपने परिचालन की शुरुआत लखनऊ स्थित अपने प्रधान कार्यालय से की। SIDBI ने रु। से अधिक के लघु क्षेत्र से संबंधित IDBI का बकाया पोर्टफोलियो ले लिया है। 4000 करोड़। सिडबी की अधिकृत पूंजी रु। 250 करोड़ रुपये इसे बढ़ाने के प्रावधान के साथ। 1000 करोड़।

सिडबी के कार्य:

SIDBI की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के संवर्धन, विकास और वित्त पोषण के लिए और समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इसने लघु उद्योग विकास निधि और राष्ट्रीय इक्विटी फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है जो पहले आईडीबीआई द्वारा प्रशासित थे।

सिडबी ने निम्नलिखित तीन क्षेत्रों को तत्काल जोर क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया है:

1. मैं। तकनीकी उन्नयन और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना।
2. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एसएसआई क्षेत्र के उत्पादों के विपणन के लिए चैनलों का विस्तार करना।
3. अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष रूप से अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना और इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवासन की जाँच करना।

सिडबी ने निम्नलिखित गतिविधियों को अपने कार्यों के रूप में रेखांकित किया है:

1. मैं। राज्य वित्तीय निगमों (SFCs), राज्य औद्योगिक विकास निगमों (SIDCs) या राज्य औद्योगिक और निवेश निगमों (SIIC) और बैंकों जैसे प्राथमिक उधार संस्थानों द्वारा विस्तारित ऋण और अग्रिमों का पुनर्वित्त।
2. बिलों की छूट और पुनर्विकास।
3. राष्ट्रीय पूंजी कोष के तहत बीज पूंजी या सॉफ्ट लोन सहायता का विस्तार, महिला उदय योजना के तहत बीज पूंजी का विस्तार।
4. एसएसआई क्षेत्र के निर्यात के वित्तपोषण के लिए प्रत्यक्ष सहायता और पुनर्वित्त प्रदान करना।
5. राज्य लघु उद्योग विकास निगम (SSIDC) को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
6. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

SIDBI ने 1992-93 के दौरान दो नई योजनाएं शुरू कीं जो इस प्रकार हैं:

मैं। मौजूदा वित्त को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने के लिए उपकरण वित्त योजना- एनटीसी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन / आधुनिकीकरण और पुनर्वित्त लेने वाली लघु-स्तरीय इकाइयाँ चलाना।

ii। लॉन्च की गई दूसरी नई योजना वेंचर कैपिटल फंड है जो विशेष रूप से रुपये की शुरुआती कॉर्पस के साथ छोटे पैमाने की इकाइयों के लिए है। 10 करोड़ रु। इसका उद्देश्य नवीन, स्वदेशी और अन्य प्रौद्योगिकियों के आधार पर टेक्नोक्रेट और अन्य उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित नए उपक्रमों को उद्यम पूंजी समर्थन का विस्तार करना था।

6. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD):

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत ग्रामीण विकास और सुरक्षित समृद्धि को बढ़ावा देना।

इसकी स्थापना पर, नाबार्ड ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का पूरा कार्यभार संभाला है और रिजर्व बैंक से राज्य सहकारी ग्रामीण बैंकों के संबंध में अपने पुनर्वित्त कार्यों को संभाला है। यह बैंक अब केंद्र सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकारों और छोटे उद्योगों, गाँव और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण शिल्पों आदि के विकास में लगी संस्थाओं और विभिन्न नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए समन्वय के साथ समन्वय करने वाली एजेंसी है। ग्रामीण ऋण से संबंधित कार्यक्रम।

नाबार्ड की राजधानी रु। 500 करोड़, समान अनुपात में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा सब्सक्राइब किए गए।

नाबार्ड का प्रबंधन:
अधिनियम के संदर्भ में, निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अलावा, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के तीन निदेशक, केंद्र सरकार के तीन अधिकारी, राज्य सरकारों के दो अधिकारी और ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, हस्तशिल्प और गांव और कुटीर उद्योगों के विशेषज्ञों के पांच निदेशक शामिल हैं। आदि और सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज के अनुभव वाले व्यक्ति।

नाबार्ड के कार्य:
मैं। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विपणन और व्यापार सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित उद्देश्यों के लिए 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

इन अल्पावधि ऋणों को नाबार्ड द्वारा मध्यम अवधि के ऋण में सूखे, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य अभियानों या दुश्मन कार्रवाई की शर्तों के तहत सात साल से अधिक नहीं किया जा सकता है।

ii। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 18 महीने से 7 साल तक की अवधि के लिए मध्यम अवधि के ऋण दे सकता है।

iii। नाबार्ड को राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों या रिज़र्व द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्थान को अधिकतम 25 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्वित्त सहायता दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने का अधिकार है। कारीगरों, लघु उद्योग, गाँव और कुटीर उद्योग आदि को ऋण देने के लिए बैंक

7. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC):
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) की स्थापना 1955 में भाड़े के आधार पर छोटे उद्यमों को मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति के उद्देश्य से की गई थी और दुकानों के विभिन्न मदों के लिए सरकारी आदेशों की खरीद में उनकी सहायता की। भाड़े की खरीद पर मशीनों की आपूर्ति एक तरह से धन की पेशकश है, विदेशी मुद्रा सुविधाओं की पेशकश, उत्पादन के बेहतर तरीकों और सभी के संयोजन के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने पर मार्गदर्शन।

NSIC अपने आप में संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को लेती है, जो सक्षम आपूर्तिकर्ताओं से मशीनों की डिलीवरी के लिए शुरू होती है। आयातित मशीनों के मामले में, NSIC विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने, आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए महानिदेशक से क्लीयरेंस प्राप्त करता है, ऋण पत्र खोलता है और सीमा शुल्क की आवश्यकता और मशीनों की निकासी के बाद देखता है।

निगम का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तथा ग्यारह शाखा कार्यालय हैं। दिल्ली में इसका एक केंद्रीय संपर्क कार्यालय और डिपो और उप-केंद्र हैं।

NSIC के कार्य:
एनएसआईसी ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने का चुनौतीपूर्ण काम लगभग खरोंच से किया है और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

एनएसआईसी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
1. मैं। लघु उद्योगों को सहायक इकाइयों के रूप में बड़े पैमाने पर उद्योगों के रूप में विकसित करना।
2. लघु उद्योगों को भाड़े-खरीद के आधार पर मशीनें उपलब्ध कराना।
3. केंद्र सरकार के स्टोर खरीद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छोटे उद्यमों की सहायता करना।
4. विपणन सुविधाओं के साथ छोटे उद्योगों की सहायता करना।
5. उनके डिपो के माध्यम से बुनियादी कच्चे माल को वितरित करने के लिए।
6. विशिष्ट उद्योगों में वास्तविक छोटे पैमाने के उपयोगकर्ताओं के लिए घटकों और भागों को आयात और वितरित करने के लिए।
7. औद्योगिक सम्पदा का निर्माण करना और प्रोटोटाइप उत्पादन सह-प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना और चलाना।

8. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC):
खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1953 में खादी और ग्रामोद्योग के विकास और ग्रामीण रोजगार के अवसरों में सुधार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। गतिविधियों की इसकी विस्तृत श्रृंखला में कारीगरों का प्रशिक्षण, कच्चे माल की खरीद के लिए सहायता का विस्तार, तैयार उत्पादों का विपणन और रियायती शर्तों पर उत्पादकों को बेहतर उपकरण, उपकरणों और मशीनरी के निर्माण और वितरण की व्यवस्था शामिल है।

KVIC खादी और ग्रामोद्योग को सहायता प्रदान करता है जिसके लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उपयोगी सामान के निर्माण के लिए आदर्श रूप से अनुकूल होता है। कई निर्दिष्ट गाँव उद्योग हैं जैसे अनाज और दालों का प्रसंस्करण, चमड़ा, माचिस, गुड़ और खांडसारी, अखाद्य तेल और साबुन, मधुमक्खी पालन, गाँव के बर्तन, बढ़ईगीरी और लोहार आदि।

KVIC की नीतियों और कार्यक्रमों को राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 और औद्योगिक सहकारी समितियों के तहत राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। केवीआईसी द्वारा सीधे पहाड़ी, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में नए उद्योगों को विकसित करने जैसे अग्रणी कार्य शामिल हैं।

राज्य सरकारों के उद्योग निदेशालय:
एसएसआई एक राज्य विषय है और इसलिए, एसएसआई को सहायता की योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक राज्य में उद्योग

निदेशालय विशेष रूप से सामान्य और लघु उद्योगों में उद्योगों के विकास से संबंधित कार्य करते हैं।

प्रत्येक निदेशालय को राज्य मुख्यालय पर प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों के साथ रखा गया है। जिला स्तर पर विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों की देखभाल के लिए जिला स्तर पर DIC (जिला उद्योग केंद्र) हैं। राज्य निदेशालय विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएँ, उत्पादन योजनाएँ और सामान्य सुविधाएँ योजनाएँ चलाते हैं।

वे औद्योगिक संपदाओं में विकसित औद्योगिक भूमि और कारखाने के शेड की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, दुर्लभ कच्चे माल के कोटा आवंटित करते हैं, आयात आवश्यकताओं को प्रमाणित करते हैं और औद्योगिक सहकारी समितियों को व्यवस्थित करते हैं। उनके कार्य विविध हैं और विकास और विविधता के साथ विकसित हुए हैंलघु क्षेत्र का आयन।

औद्योगिक संपदा:

विकासशील देशों को अपने तेजी से औद्योगिकीकरण और संतुलित विकास के लिए संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक संस्थागत उपाय है औद्योगिक संपदा। 'औद्योगिक संपदा' शब्द को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक शहर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक टाउनशिप आदि।

एक औद्योगिक संपत्ति भूमि का एक हिस्सा है जो औद्योगिक उद्यमों के समुदाय के उपयोग के लिए एक व्यापक योजना के अनुसार उप-विभाजित और विकसित है। यह मानक इकाइयों के भवनों और उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं की पेशकश करने वाली औद्योगिक इकाइयों की योजनाबद्ध क्लस्टरिंग है।

एक औद्योगिक संपत्ति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. मैं। यह उप-विभाजित और फैक्ट्री भूखंड और शेड में विकसित भूमि का एक पथ है।
2. यह कई सामान्य सुविधाएं या बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि पानी, बिजली, परिवहन, उपकरण कक्ष, प्रशिक्षण, बैंक, डाकघर, मरम्मत और रखरखाव आदि।
3. यह औद्योगिक इकाइयों का एक नियोजित क्लस्टरिंग है।
4. इसे औद्योगिकीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास के उपकरण के रूप में तैयार किया गया है।
5. इसे शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है।
6. यह सरकार या सहकारी समितियों द्वारा या निजी एजेंसियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

एक औद्योगिक संपत्ति उद्यमिता के विकास के लिए एक बहुउद्देशीय व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके, यह लघु उद्योगों के विकास के लिए एक जन्मजात जलवायु प्रदान करता है।

आम सुविधाओं के उपयोग के कारण समय और प्रयास में कम निवेश और बचत होती है। इन उद्योगों में बेहतर परिवहन सुविधा, प्रशिक्षित श्रम की उपलब्धता, बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति, परीक्षण और मरम्मत की सुविधाओं तक आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता आदि हैं। यह नए उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करता है।[10]

संदर्भ

[1] लघु उद्योग की सम्पुर्ण जानकारी एवं व्यवसाय के प्रकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट

[2] लघु उद्योग में बानाये जा सकने वाले सामानों की सूची

[3] ग्रामीणों की जीवन रेखा : लघु एवं कुटीर उद्योग

[4] लघु उद्योग दिवस

[5] http://lubindia.com/certificate-of-origin-laghu-udyog-bharati/. गायब अथवा खाली |

[6] भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

[7] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत)

[8] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार)

[9] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त

[10] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान कानपुर का जालघर